RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2019-2021 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com

www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 21 APRIL TO 27 APRIL 2021 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 06 ■ अंक 35 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

अधिकारियों के पास जल्दी होगी बिना ई-वे बिल के जाने वाहनों की तत्काल जानकारी Page 3

अब तेजी से निपटेंगे चेक बाउंस के मामले, सुप्रीम कोर्ट ने दिया यह आदेश Page 4

खाद्य तेलों के बीच मक्का रिफाइंड तेल भी बना रहा है अपनी जगह, चार साल में दोगुना हुआ उत्पादन Page 7

editoria!

वृद्धि में बाधा

कोरोना महामारी की दूसरी लहर भयावह विभीषिका में बदल रही है. इसे नियंत्रित करने के लिए जरूरी पाबंदियां लगायी जा रही हैं. हालांकि पिछले साल की तरह व्यापक लॉकडाउन नहीं लगाया गया है, लेकिन रात व सप्ताहांत के कर्फ्यू, सीमित आवाजाही और कई तरह के कारोबारों पर अस्थायी रोक से आर्थिक गतिविधियों में संकुचन आ रहा है. अनेक जगहों पर कुछ दिनों के लिए लॉकडाउन भी लगाया जा रहा है. कोरोना वायरस के तेज संक्रमण को देखते हुए यह कह पाना मुश्किल है कि स्थिति कब तक सामान्य होगी. पिछले साल के आखिरी महीनों में पाबंदियों के हटाने के साथ ही कारोबार और कामकाज बहुत हद तक पहले की तरह होने लगे थे. उस वजह से बीते वित्त वर्ष की पहली दो तिमाहियों में ऋणात्मक हो चुके वृद्धि दर को बढ़ाया जा सका था. उस बढ़त के आधार पर यह अनुमान लगाया गया था कि चालू वित्त वर्ष में विकास दर दो अंकों में रहेगी और अगले वित्त वर्ष में यह दर 2019-20 के स्तर पर आ जायेगी. लेकिन महामारी की दूसरी लहर से उस उम्मीद पर पानी फिर सकता है. अब विश्व बैंक का आकलन है कि 2021-22 के वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7.5 से लेकर 12.5 प्रतिशत के दायरे में रह सकती है. इससे स्पष्ट है कि अर्थव्यवस्था को लेकर अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो गयी है. इस दायरे में आंकड़ा क्या होगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि हम कितनी जल्दी महामारी पर काबू करेंगे क्योंकि सभी अनुमानों का आधार यह भरोसा था कि देश को दूसरी लहर का सामना नहीं करना पड़ेगा. मांग और उत्पादन घटने के कारण बेरोजगारी दर भी बढ़ने लगी है. ऐसे में एक बड़ी उम्मीद मॉनसून से है, जिसके इस साल सामान्य रहने की आशा है और सूखे की कोई आशंका दूर-दूर तक नहीं है. अच्छी बारिश से फसलों की बुवाई अधिक होगी, जिससे ग्रामीण आमदनी में बढ़ोतरी होगी. समुचित उपज से खाद्य मुद्रास्फीति को भी नियंत्रित रखने में मदद मिलेगी. उल्लेखनीय है कि पिछले साल लॉकडाउन में और बाद में बड़ी मात्रा में कृषि उत्पादों के निर्यात से अर्थव्यवस्था को बहुत सहारा मिला था. अनाज के भरे भंडारों की वजह से करोड़ों गरीब परिवारों को मुफ्त या सस्ता राशन मुहैया कराया जा सका था. पिछले साल अनेक चरणों में केंद्र सरकार द्वारा घोषित वित्तीय राहत, छूट, कल्याण कार्यक्रमों आदि से भी आर्थिकी को मदद मिली थी. यह भी ध्यान रखना होगा कि कृषि क्षेत्र से अपेक्षाओं पर खाद्य पदार्थों के वैश्विक मूल्यों का भी असर होगा तथा सरकारी व्यय की भी इसमें बड़ी भूमिका होगी. यही कारण है कि कृषि समेत विभिन्न क्षेत्रों को सरकारी मदद उपलब्ध कराने की मांग उठने लगी है. मौजूदा स्थिति में कुछ बजट प्रावधानों को फौरी तौर पर लागू करने की जरूरत पड़ सकती है. फिलहाल हमारा पूरा जोर बचाव के उपायों और टीकाकरण बढ़ाने पर होना चाहिए.

बीते वित्त वर्ष में कच्चे तेल का उत्पादन पांच प्रतिशत, गैस उत्पादन आठ प्रतिशत घटा

नयी दिल्ली। एजेंसी

देश का कच्चे तेल का उत्पादन बीते वित्त वर्ष 2020-21 में पांच प्रतिशत घट गया। मंगलवार को जारी सरकारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। इस दौरान गैस के उत्पादन में भी आठ प्रतिशत की गिरावट आई। आंकड़ों से पता चलता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के साथ निजी क्षेत्र की कंपनियों का उत्पादन भी नीचे आया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार बीते वित्त वर्ष में कच्चे तेल का उत्पादन घटकर 3.05 करोड़ टन रह गया, जो इससे पिछले वित्त वर्ष में 3.21 करोड़ टन रहा था। वित्त वर्ष के दौरान ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन (ओएनजीसी) का उत्पादन दो प्रतिशत घटकर 2.02 करोड़ टन रह गया। बीते साल कोरोना वायरस महामारी की वजह से लगाए गए लॉकडाउन के चलते कंपनी के कुछ उत्पादन क्षेत्र बंद रहे थे। ऑयल इंडिया (ओआईएल) का उत्पादन 5.4 प्रतिशत घटा। वहीं निजी क्षेत्र की कंपनी वेदांता की केयर्न के परिचालन वाले क्षेत्रों का उत्पादन 12.6 प्रतिशत घट गया।आंकड़ों के अनुसार, बीते वित्त वर्ष में प्राकृतिक गैस का उत्पादन आठ प्रतिशत घटकर 28.67 अरब घनमीटर रह गया। 2019-20 में यह 31.18 अरब घनमीटर था। हालांकि, मार्च महीने में गैस का उत्पादन बढ़ा है। इस दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज-बीपी ने अपने केजी बेसिन क्षेत्र से उत्पादन शुरू किया। आंकड़ों के अनुसार नए क्षेत्र डी-34 (रिलायंस-बीपी के केजी-डी6 ब्लॉक) से उत्पादन शुरू होने से मार्च का गैस उत्पादन बढ़ा है। इस क्षेत्र से उत्पादन दिसंबर, 2020 में 13 लाख घनमीटर प्रतिदिन के साथ शुरू हुआ था। मार्च, 2021 में यह बढ़कर 96 लाख घनमीटर प्रतिदिन हो गया। महामारी की वजह से आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होने के चलते देश में ईंधन की मांग घटी है। इस वजह से देश की सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों ने 2020-21 में 13 प्रतिशत कम यानी 22.17 करोड़ टन कच्चे तेल का प्रसंस्करण किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज की गुजरात के जामनगर की दो रिफाइनरियों ने 11.5 प्रतिशत कम यानी 6.09 करोड़ टन कच्चे तेल का प्रसंस्करण किया। रोसनेफ्ट की अगुवाई वाली नायरा एनर्जी ने 13 प्रतिशत कम यानी 1.7 करोड़ टन का प्रसंस्करण किया। सार्वजनिक क्षेत्र की इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) का कच्चे तेल का प्रसंस्करण करीब 12 प्रतिशत घटकर 12.75 करोड़ टन रह गया।

ऑक्सीजन सप्लाई के लिए रतन टाटा ने उठाया बड़ा कदम, लोग खूब कर रहे तारीफ

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में देश के कई हिस्सों से ऑक्सीजन कमी की खबरें आई थीं। ऐसे में टाटा समूह ने भारतीयों की परेशानी को कुछ हद तक कम करने का बीड़ा उठाया है। समूह ने लिक्विड ऑक्सीजन की आवाजाही के लिए 24 क्रायोजेनिक कंटेनर्स आयात करने का फैसला किया है। कहा जा रहा है कि इससे देश में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी। टाटा समूह ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से लिखा 'भारत के लोगों से पीएम नरेंद्र मोदी की अपील प्रशंसनीय है और हम टाटा समूह में, COVID-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए यथासंभव प्रयास कर रहे हैं। ऑक्सीजन संकट को कम करने के लिए, यह स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने का एक प्रयास है।' एक अन्य ट्वीट में कंपनी ने लिखा कि टाटा समूह तरल ऑक्सीजन के परिवहन के लिए 24 क्रायोजेनिक कंटेनरों का आयात कर रहा है। मंगलवार को ही समूह ने लिखा था कि ऑक्सीजन संकट को देखते हुए वे भारत के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए पूरे प्रयास कर रहे हैं। खास बात है कि इससे एक दिन पहले ही टाटा स्टील ने घोषणा की थी कि वे राज्य सरकारों और अस्पतालों को रोज 200-300 टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन भेज रहे हैं।

कोरोना से 12 फीसदी कम हुई डीजल की मांग

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

कोरोना वायरस संक्रमण रोकने के लिए लगाई गई पाबंदियों का ईंधन की मांग पर नकारात्मक असर पड़ा है। वर्ष 2020-21 में पिछले साल के मुकाबले पेट्रोल डीजल की मांग कम हुई है। हालांकि, लॉकडाउन खत्म होने के बाद आर्थिक गतिविधियां शुरु होने पर पिछले छह माह के दौरान पेट्रोल-डीजल की मांग वर्ष 2019-20 के मुकाबले ज्यादा रही है। पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी) के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले साल खपत में सबसे ज्यादा कमी डीजल में आई है। डीजल की मांग करीब 12 फीसदी कम हुई। हालांकि, मार्च में डीजल की मांग पिछले साल मार्च के मुकाबले करीब 28 प्रतिशत ज्यादा थी। पिछले साल सरकार ने 22 मार्च को जनता कर्फ्यू और उसके बाद लॉकडाउन का ऐलान किया था। पेट्रोल की खपत में भी पिछले साल लगभग सात फीसदी की कमी आई हैं। वहीं, एलपीजी की मांग में बहुत मामूली वृद्धि दर्ज की गई। सरकार ने कोरोना महामारी से निपटने में लोगों की मदद करने के लिए उज्ज्वला योजना का लाभार्थियों को मुफ्त गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का फैसला किया था। इसकी वजह से रसोई गैस की मांग पिछले साल के बराबर रही। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को रोकने के लिए बढ़ती पाबंदियों की वजह से ईंधन की मांग में फिर कमी आनी शुरू हो गई है। अप्रैल के पहले पखवाड़े में डीजल और पेट्रोल की मांग कम हुई है। सीएनजी की मांग पर असर पड़ा है पर एलपीजी की मांग अभी बरकरार है। अनुमान के मुताबिक पेट्रोल की मांग पांच फीसदी और डीजल की खपत तीन प्रतिशत कम हुई है। करीब दो दशक में ऐसा पहली बार हुआ है, जब देश में ईंधन की खपत कम हुई है। पीपीएसी के पास 1998-99 के बाद के पेट्रोलियम डीजल की खपत के तमाम आंकड़े मौजूद हैं। कोरोना संक्रमण की दस्तक से पहले पेट्रोलियम पदार्थों की मांग में करीब 9 फीसदी की वृद्धि का रुझान था पर कोरोना वायरस की वजह से गतिविधियां थम गई और मांग कम हो गई।

कोरोना ने सिखाया छह नहीं 12 महीने का बनाएं आपात कोष

नई दिल्ली। एजेंसी

कोरोना की दूसरी लहर ने सबकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। पिछले साल मार्च लेकर मई तक पूर्ण लॉकडाउन के बाद कई मोर्चों पर मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। कंपनियों की बंदी से छंटनी करनी पड़ी और रोजगार के अवसर भी घटे। पिछले एक साल से बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार बैठे हैं। ऐसे में वित्तीय मुसीबत से बचने के लिए कोरोना ने सिखा दिया है कि अब छह नहीं 12 महीने का आपात कोष (इमर्जेंसी फंड) बना कर रखना ही समझदारी भरा फैसला है।

क्या है आपात कोष

यह ऐसी बचत राशि है जो आपकी नौकरी छूट जाने की स्थिति में आपके हर माह के जरूरी खर्च के लिए पर्याप्त होती है। आपके हर माह का खर्च तय होता है। इसमें रसोई से लेकर बच्चों की स्कूल फीस, कर्ज की ईएमआई और कुछ अन्य खर्च होते हैं। नौकरी छूट जाने पर भी यह खर्च आप बंद नहीं कर सकते हैं। हालांकि, इमर्जेंसी फंड कितनी अवधि का को इसके लिए कोई मानक तय नहीं है और यह आपकी वित्तीय स्थिति पर निर्भर करता है। इसके बावजूद कम से कम एक साल के लिए इमर्जेंसी फंड जरूर रखें।

बचत खाता को न समझें आपात कोष

सामान्य तौर पर हम बचत खाता में जमा को इमर्जेंसी फंड मानने की गलती कर बैठते हैं। जबकि उसमें से लगातार सभी काम के लिए राशि निकलती रहती है। वित्तीय सलाहकारों का कहना है कि इमर्जेंसी फंड को अलग-अलग कई विकल्पों में निवेश करके रखना चाहिए। इसमें बचत खाता के अलावा, लिक्विड फंड और छोटी अवधि की एफडी शामिल है।

लिक्विड फंड में करें निवेश

लिक्विड फंड भी छोटी अवधि का होता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इमर्जेंसी फंड का एक हिस्सा इसमें जरूर रखना चाहिए। म्यूचुअल फंड कंपनियां लिक्विड फंड की पूंजी 91 दिन की परिपक्वता वाले तय अवधि (टेड उत्पाद) वाले उत्पादों में निवेश करती हैं। इसकी वजह से बाजार में तेज उतार-चढ़ाव आने पर इनके रिटर्न पर ज्यादा असर नहीं पड़ता है।

छोटी अवधि की कई एफडी कराएं

इमर्जेंसी फंड के लिए बड़ी राशि की एक एफडी कराकर रखना समझदारी भरा फैसला नहीं है। वित्तीय विशेषज्ञों का कहना है कि इसके लिए छोटी राशि की एक से तीन माह की अलग-अलग कई एफडी रखें। साथ ही अवधि पूरी होने पर इसे आगे बढ़वाते रहें। इससे आपके पास हर समय पैसे की उपलब्धता रहेगी और समय से पहले एफडी बंद करने की स्थिति में शुल्क चुकाने से भी बच जाएंगे।

आर्थिक परिदृश्य निराशाजनक, टीकाकरण की रफ्तार करनी होगी तेज : क्रिसिल

नई दिल्ली। एजेंसी

देश में लगातार कोविड-19 संक्रमण के 2.5 लाख से अधिक मामले आ रहे हैं। इस चिंताजनक स्थिति के बीच एक रिपोर्ट में आगाह किया गया है कि लोगों की आवाजाही और कुछ कारोबार क्षेत्रों पर सीमित अंकुशों के बावजूद आर्थिक परिदृश्य निराशाजनक दिख रहा है। बिजली की खपत और ई-वे जीएसटी बिल संग्रहण पहले की तुलना में सुस्त पड़ा है। रिपोर्ट में टीकाकरण की रफ्तार को तेज करने पर जोर दिया गया है। साप्ताहिक आधार पर टीकाकरण सुस्त हुआ है। क्रिसिल के मंगलवार को जारी एक नोट में कहा गया है कि संक्रमण के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और अब अधिक से अधिक राज्य स्थानीय स्तर पर लोगों की आवाजाही और कारोबार पर अंकुश लगा रहे हैं। बिजली की खपत से लेकर जीएसटी ई-वे बिल संग्रहण में इसका असर दिख रहा है।

क्रिसिल ने कहा कि राहत की बात यह है कि विनिर्माण और निर्माण गतिविधियों का परिचालन हो रहा है। ज्यादातर राज्यों में सामाजिक दूरी उपायों के साथ यात्रा और घूमने-फिरने से जुड़ी सेवाओं की अनुमति है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चिंता की बात टीकाकरण की सुस्त रफ्तार है। 18 अप्रैल को समाप्त सप्ताह में प्रतिदिन प्रत्येक 10 लाख लोगों पर 2,408 को टीका लगाया गया। इससे पिछले यानी 11 अप्रैल को समाप्त सप्ताह में यह आंकड़ा 2,554 का था।

रिपोर्ट कहती है कि 18 अप्रैल तक 45 से 65 आयु वर्ग में सिर्फ 16.4 प्रतिशत आबादी को टीका लगा है। वहीं 65 साल और उससे अधिक के आयुवर्ग में 33.1 प्रतिशत लोगों को टीका लगाया गया है। भारत में महामारी की स्थिति काफी खराब है। 12 से 18 अप्रैल के दौरान प्रतिदिन दो लाख से अधिक नए संक्रमण के मामले आए। इससे भारत संक्रमण के नए मामलों में ब्राजील को पीछे छोड़कर सबसे आगे निकल गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि महाराष्ट्र में 18 अप्रैल को समाप्त सप्ताह में संक्रमण के नए मामलों में काफी गिरावट आई है। वहीं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली में इनमें उल्लेखनीय इजाफा हुआ है। संक्रमण के नए मामलों में 11 अप्रैल को समाप्त सप्ताह में महाराष्ट्र की हिस्सेदारी 42.3 प्रतिशत थी जो 18 अप्रैल को समाप्त सप्ताह में घटकर 28.2 प्रतिशत पर आ गई।

Oxygen crisis in India

...तो यह है देश में ऑक्सीजन की किल्लत की असली वजह!

नई दिल्ली। एजेंसी

देश में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती तादाद के बीच राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में ऑक्सीजन की भारी कमी हो गई है। कोरोना के गंभीर मरीजों के इलाज में ऑक्सीजन की अहम भूमिका है। लेकिन इस संकट के बावजूद भारत ने वित्त वर्ष 2020-21 के पहले 10 महीनों में पूरे वित्त वर्ष 2019-20 की तुलना में दोगुना ऑक्सीजन का निर्यात किया। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के आंकड़ों में यह खुलासा हुआ है। सच्चाई यह है कि इस भारत कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा 3 प्रभावित देशों में शामिल था। बिजनसटुडे के मुताबिक अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 के दौरान भारत ने 9301 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का निर्यात किया जिससे उसे 8.9 करोड़ रुपये की कमाई हुई। इसकी तुलना में भारत ने वित्त वर्ष 2019-20 में कुल 4514 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का निर्यात किया था जिससे 5.5 करोड़ रुपये की कमाई हुई थी।

मेडिकल ऑक्सीजन की भारी मांग

देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच मेडिकल ऑक्सीजन की भारी मांग है। मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राजधानी के कुछ अस्पतालों में ऑक्सीजन का कुछ घंटे का ही स्टॉक रह गया है। देश के कई अन्य राज्यों में भी यही स्थिति है। कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित महाराष्ट्र ने राज्य में मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए केंद्र से मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने की मांग की थी। इसके अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और देश की कई दूसरे राज्य भी ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहे हैं।

रिलायंस इंडस्ट्रीज, सेल, टाटा स्टील और आर्सेलरमित्तल निप्पन स्टील इंडिया सहित कई कंपनियों ने देश में ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए मदद का हाथ बंटाया है। इस्पात मंत्रालय के मुताबिक सरकारी और निजी क्षेत्र की स्टील कंपनियों के 28 ऑक्सीजन प्लांट रोजाना 1500 टन मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहे हैं। टाटा ग्रुप ने लिक्विड ऑक्सीजन ले जाने के लिए 24 क्रायोजेनिक कंटेनर आयात करने का फैसला किया है।

फिर शुरू हुआ WFH, कोरोना की दूसरी लहर से कंपनियों ने बड़े शहरों में बंद किए ऑफिस

नई दिल्ली। एजेंसी

देश में कोरोना की दूसरी लहर, कई राज्यों में लॉकडाउन और कर्फ्यू से पूरे देश में कंपनियों ने बड़े शहरों में अपने ऑफिस बंद कर दिए हैं और उनके कर्मचारी एक बार फिर पूरी तरह घर से काम (Work from home) करने लगे हैं। जिन शहरों में अभी लॉकडाउन नहीं है, वहां भी कंपनियों अपने कर्मचारियों को घर से काम करने को कह रही हैं।

Infosys, TCS, ITC, IBM, Raymond, InMobi, Motilal Oswal Financial Services, Dunzo, Deloitte, SAP India, ManpowerGroup, Quess Corp, BookMyShow, PolicyBazaar और RPG Enterprises सहित कई कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को घर से काम करने को कहा है। कंपनियां ने केवल कोरोना प्रभावित इलाकों में अपनी कर्मचारियों को घर से काम करने को कह रही हैं बल्कि जिन इलाकों में कोरोना का ज्यादा असर नहीं है, वहां भी उन्हें ऐहतियात के तौर पर घर से काम करने की सलाह दे रही हैं।

कौन कंपनी कर रही है कर्मचारियों का वैक्सीनेशन

देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इन्फोसिस के अधिकांश कर्मचारी घर से ही काम कर रहे हैं। कंपनी के सीओओ प्रवीण राव ने उन्हें एक ईमेल भेजकर घर पर ही रहने की सलाह दी है।

आईटीसी के हेड (कॉरपोरेट ह्यूमन रिसॉर्सेज) अमिताभ मुखर्जी के मुताबिक कंपनी ने अपने ऑफिस बंद कर दिए हैं और कर्मचारियों को घर से ही काम जारी रखने को कहा है। टीसीएस और आईबीएम ने जून के अंत तक अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की सलाह दी है।

SAP India Labs ने भी सभी कर्मचारियों को घर से काम करने को कहा है। इनमें 10 फीसदी वो कर्मचारी भी हैं जिन्होंने हाल में ऑफिस आना शुरू किया था। कंपनी ने साथ ही बेंगलूरु कैंपस में पात्र कर्मचारियों का वैक्सीनेशन भी शुरू किया है। रेमंड के प्रेजिडेंट (HR) के ए नारायण ने कहा कि हम ऐहतियाती कदम उठाने में सक्रिय रहे और कर्मचारियों को 5 अप्रैल से ही सारा काम घर से करने की सलाह दी। स्थिति के सामान्य होने तक ऐसा ही रहेगा।

आईटी और आईटीईएस इंडस्ट्री बेहतर स्थिति में

इंडस्ट्री के अधिकारियों का कहना है कि इस बार आईटी और आईटीईएस इंडस्ट्री (IT and ITes Industry) लॉकडाउन से निपटने के लिए बेहतर स्थिति में है क्योंकि उनके अधिकांश कर्मचारी पहले ही घर से काम कर रहे हैं। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नई दिल्ली सहित देश के कई हिस्सों में लॉकडाउन लगाया गया है। इंडस्ट्री के एक अधिकारी ने कहा कि महाराष्ट्र जैसे राज्यों में आईटी को आवश्यक सेवाओं की सूची में शामिल किया गया है। दिल्ली में लॉकडाउन का ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इंडस्ट्री के अधिकांश लोग नोएडा और गुड़गांव में रहते हैं। कुछ कंपनियों ने 10-15 फीसदी कर्मचारियों को बुलाना शुरू किया था लेकिन कोरोना के मामले बढ़ने से एक बार फिर वे घर से काम कर रहे हैं।

अधिकारियों के पास जल्दी होगी बिना ई-वे बिल के जाने वाहनों की तत्काल जानकारी

नयी दिल्ली। एजेंसी

सरकार बिना ई-वे बिल के जा रही वाहनों के मामले में जीएसटी अधिकारियों को वास्तविक समय पर रिपोर्ट उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने जा रही है। इससे टोल प्लाजा पर ट्रकों को पकड़ने और जीएसटी (माल एवं सेवा कर) चोरी रोकने में मदद मिलेगी।

इसके साथ कर अधिकारियों को उन ई-वे बिलों की विश्लेषण रिपोर्ट भी उपलब्ध करायी जाएगी जहां वस्तुओं की ढुलाई नहीं हो रही। इससे अधिकारियों को 'सर्कुलर ट्रेडिंग' (इनपुट टैक्स क्रेडिट के उपयोग के लिये फर्जी बिक्री सौदा दिखाने की धोखाधड़ी) के मामलों को पहचानने में मदद मिलेगी। इससे कर चोरी के लिए ई-वे बिल के पुनर्चक्रण की भी रिपोर्ट मिलेगी जिससे अधिकारियों को कर चोरी करने वालों का पता लगाने में मदद मिलेगी। माल एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के तहत अप्रैल 2018 से 50,000 रुपये से अधिक मूल्य की वस्तुओं को एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजने के लिए ई-वे बिल अनिवार्य है। हालांकि सोने को इससे छूट दी गयी है। सरकार अब जीएसटी अधिकारियों के लिये आरएफआईडी (रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेन्टिफिकेशन) पर वास्तविक समय और विश्लेषण रिपोर्ट पर काम कर रही है। इससे ई-वे बिल प्रणाली का दुरूपयोग कर रहे लोगों पर शिकंजा चढ़ाया जा सकेगा।

ई-वे बिल पर एक रिपोर्ट में सरकार ने कहा है कि मार्च 2021 तक की तीन साल की अवधि में 180 करोड़ ई-वे बिल सृजित किये गये हैं। इसमें से केवल 7 करोड़ बिलों का सत्यापन अधिकारियों ने किया है। 'ई-वे बिल-तीन साल की यात्रा' शीर्षक से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2020-21 में 61.68 करोड़ ई-वे बिल सृजित हुए। इनमें से 2.27 करोड़ का सत्यापन किया गया। वहीं वित्त वर्ष 2019-20 में 62.88 करोड़ ई-वे बिल का सृजन हुआ। इसमें से कर अधिकारियों ने 3.01 करोड़ को सत्यापन के लिये चुना। जिन पांच राज्यों ने सर्वाधिक ई-वे बिल सृजित किये, वे गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाण, तमिलनाडु और कर्नाटक हैं। जिन पांच क्षेत्रों में पिछले तीन साल में अधिकतम संख्या में ई-वे बिल सृजित किये गये, वे कपड़ा, इलेक्ट्रिक मशीनरी, मशीनरी और यांत्रिक उपकरण, लोहा और इस्पात तथा वाहन हैं।

सरकार ने एक जनवरी, 2021 से आरएफआईडी/फास्टटैग को ई-वे बिल प्रणाली से एकीकृत किया है। इसके तहत ट्रांसपोर्टर के लिये अपने वाहन में आरएफआईडी टैग का होना जरूरी है। साथ ही वस्तुओं की ढुलाई के लिये सृजित ई-वे बिल का ब्योरा आरएफआईडी में अपलोड करना आवश्यक है। इससे जब भी संबंधित वाहन आरएफआईडी टैग को पढ़ने वाले उपकरण से युक्त राजमार्गों से गुजरता है, पूरा ब्योरा सरकारी पोर्टल पर अपलोड हो जाता है। बाद में इस सूचना का उपयोग राजस्व अधिकारी जीएसटी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा की गयी आपूर्ति के सत्यापन में करते हैं।

LIC ने बनाया नया रिकॉर्ड! जोड़े लाखों नए ग्राहक

2020-21 में बेची 1.84 लाख करोड़ रुपये की पॉलिसी

नई दिल्ली। एजेंसी

देश की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (थ्ध्ग्) ने मंगलवार को कहा कि उसने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्त वर्ष में नये कारोबार से 1.84 लाख करोड़ रुपये की प्रीमियम आय प्राप्त की जो अब तक का सबसे ज्यादा है। एलआईसी ने कहा कि आंकड़ा अस्थायी है। कंपनी की बाजार हिस्सेदारी मार्च 2021 में पॉलिसी संख्या के हिसाब से 81.04 प्रतिशत रही। इसके अलावा पूरे वित्त वर्ष में हिस्सेदारी 74.58 प्रतिशत रही। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान बीमा कंपनी ने व्यक्तिगत बीमा कारोबार के पहले साल की प्रीमियम आय के रूप में 56,406 करोड़ रुपए प्राप्त किये। यह 2019-20 के मुकाबले 10.11 फीसदी अधिक है।

मार्च में बेची 46.72 लाख पॉलिसी

पहले साल के प्रीमियम के रूप में उसकी बाजार हिस्सेदारी 64.74 फीसदी और पूरे वित्त वर्ष 66.18 फीसदी रही। कंपनी ने वर्ष के दौरान कुल 2.10 करोड़ पॉलिसी बेची जिसमें से 46.72 लाख अकेले मार्च में ही बेची गई। पिछले साल मार्च के मुकाबले इसमें 298.82 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। एलआईसी की विज्ञप्ति के अनुसार वर्ष के दौरान उसने रिकॉर्ड 31,795 नई पॉलिसी बेची। बीमा कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष में 3,45,469 नए एजेंट जोड़े। इससे उसके एजेंट की संख्या बढ़कर 13,53,808 हो गयी।

इस साल निर्यात सकारात्मक दायरे में रहेगाः वाणिज्य सचिव

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

वाणिज्य सचिव अनूप वधावन ने मंगलवार को बताया कि देश का निर्यात पिछले कुछ महीनों में तेजी से आगे बढ़ रहा है और उन्हें उम्मीद है कि मौजूदा वित्तवर्ष में इसमें और भी तेजी देखने को मिलेगी। उनके मुताबिक पिछले साल अप्रैल में निर्यात में बड़ी गिरावट दर्ज की गयी थी लेकिन धीरे-धीरे चीजें सुधरनी शुरू हुई और निर्यात सकारात्मक दायरे में आया। यही वजह है कि अब पूरा भरोसा है कि वित्त वर्ष 2021-22 में देश मजबूत वृद्धि के रास्ते पर होगे। अनूप वधावन ने कहा इसमें कोई भी संदेह नहीं है लेकिन मैं वृद्धि के आंकड़े का कोई अनुमान नहीं जताना चाहता। आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर 2020 से देश के निर्यात में सकारात्मक वृद्धि जारी है। इस साल मार्च में निर्यात 60.29 प्रतिशत बढ़कर 34.45 अरब डॉलर रहा। हालांकि, 2020-21 में निर्यात 7.26 प्रतिशत घटकर 290.63 अरब डॉलर रहा। अमेरिका और चीन के साथ व्यापार अंतर के बारे में पूछे जाने पर वाणिज्य सचिव ने कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 में अमेरिका के साथ व्यापार अधिशेष की स्थिति रही जबकि चीन के साथ व्यापार घाटे में सुधार हुआ है। अमेरिका को भारत का निर्यात वित्त वर्ष 2019-20 में 53 अरब डॉलर और 2020-21 में 51 अरब डॉलर रहा। वहीं अमेरिका से आयात 2019-20 में 35.8 अरब डॉलर और 2020-21 में 28 अरब डॉलर रहा। चीन को भारत का निर्यात 2019-20 में 16.6 अरब डॉलर और 2020-21 में 21.2 अरब डॉलर रहा। वहीं चीन से आयात 2019-20 में 65 अरब डॉलर और 2020-21 में भी मोटे तौर पर इतना ही रहा।

सुप्रीम कोर्टः जीएसटी कानून के तहत बैंक खाते, संपत्ति जब्ती का आदेश कठोर फैसला

नई दिल्ली। एजेंसी

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) कानून के तहत किसी व्यक्ति के बैंक खाते व संपत्ति को जब्त करने का आदेश देना कठोर फैसला है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि प्राधिकरण इसका इस्तेमाल अनियंत्रित तरीके से नहीं कर सकता।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने कहा कि कार्यवाही लंबित होने के दौरान अस्थायी रूप से संपत्ति आदि की जब्ती का मतलब यह है कि अंतिम देय राशि को लेकर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। ऐसे में अस्थायी रूप से जब्ती, कानून में दी गई प्रक्रिया व शर्तों के अनुरूप ही होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने राधाकृष्ण इंडस्ट्रीज द्वारा हिमाचल प्रदेश के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर प्रदेश के जीएसटी अधिनियम की धारा-83 की व्याख्या करते हुए ये बातें कहीं। शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा कि कमिश्नर को इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि इस तरह के प्रावधान लोगों की संपत्ति पर पूर्वव्यापी हमला करने के लिए नहीं है। यह तब किया जाना चाहिए, जब राजस्व के हितों की रक्षा के लिए ऐसा करना बेहद आवश्यक हो।

इससे पहले हाईकोर्ट ने अथॉरिटी द्वारा अस्थायी रूप से संपत्ति जब्त करने के निर्णय के खिलाफ राधाकृष्ण इंडस्ट्रीज की रिट याचिका खारिज कर दी थी। कंपनी पर 5.03 करोड़ रुपये की देनदारी थी। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर राधाकृष्ण इंडस्ट्रीज ने कहा था कि धारा-83 के तहत जब्ती की कार्रवाई का प्रावधान बेरहम व कठोर है। इससे पहले सात अप्रैल को फैसला सुरक्षित रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद की मंशा थी कि जीएसटी नागरिकों के अनुकूल कर ढांचा हो लेकिन जिस तरह से इसे देश भर में लागू किया जा रहा है, वह इसके उद्देश्य को खत्म कर रहा है।

News यू केन USE

दाम घटने, शुल्क कटौती से मार्च में सोने का आयात बढ़कर 160 टन पर पहुंचा: जीजेईपीसी

मुंबई। रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी) ने मंगलवार को कहा कि शुल्क कम कर 7.5 प्रतिशत करने, बहुमूल्य धातु की कीमत में कमी तथा निर्यात बाजारों की मांग बढ़ने से मार्च में सोने का आयात बढ़कर 160 टन हो गया। जीजेईपीसी के आंकड़ों के मुताबिक 2019-20 के दौरान मार्च में सोने का आयात 28.09 टन हुआ था। जीजेईपीसी ने कहा कि सोने के आयात में वृद्धि मुख्य रूप से लॉकडाऊन में ढील, भारत में शादी विवाह के मौसम, व्यापार और उपभोक्ता धारणा में सुधार आने से हुई। इसके साथ ही हाल ही में सोने की कीमतों में भारी गिरावट आने के बाद अमेरिका, ब्रिटेन जैसे निर्यात बाजारों से रत्न और आभूषण उत्पादों की मांग में वृद्धि के कारण हुई है। जीजेईपीसी का मानना है कि उक्त अवधि में घरेलू बाजार और विभिन्न देशों में त्यौहारों का समय होने, खनन और निर्यात गतिविधियों के फिर से शुरु होने, घरेलू और वैश्विक बाजार में उत्पादन गतिविधियों के फिर से शुरू होने, कोरोना टीके को विकास तथा टीकाकरण की शुरुआत तथा यात्रा में छूट जैसे कई वजहों से सोने की मांग में वृद्धि हुई। जीजेईपीसी के अध्यक्ष कॉलिन शाह ने कहा, 'हमें एक उचित निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए आगामी महीनों में समग्र बाजार के रुझान का समग्र रूप से निरीक्षण करना होगा।

वित्त विधेयक के संशोधनों को मंजूरी, होगा टैक्सपेयर्स की समस्याओं का निदान

नई दिल्ली। एजेंसी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त विधेयक, 2021 में किए गए आधिकारिक संशोधनों को मंगलवार को मंजूरी दे दी। इन संशोधनों का मकसद 2021-22 के लिए कर प्रस्तावों को युक्तिसंगत बनाना और चीजों को स्पष्ट करना है। प्रस्तावों को स्पष्ट करने, उसे युक्तिसंगत बनाने तथा वित्त विधेयक के प्रस्तावों को लेकर संबंधित पक्षों में चिंताओं को दूर करने के लिए संशोधन जरूरी थे। यह वित्त विधेयक 28 मार्च 2021 को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद वित्त कानून, 2021 बन गया है। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार सरकार द्वारा वित्त विधेयक, 2021 में संशोधनों का मकसद विभिन्न कर प्रसतावों पर संबंधित पक्षों की चिंताओं को दूर करना है। इसमें कहा गया है कि वित्त विधेयक 2021 में संशोधन करने का प्राथमिक उद्देश्य सरकारी खजाने में समय पर राजस्व सृजन करना और करदाताओं और अन्य पक्षों द्वारा उठाए गए मुद्दों का समाधान करना है।

टीकाकरण की उम्र घटाकर 18 साल करने से लोगों का भरोसा बढ़ेगा: एसोचैम

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

उद्योग मंडल एसोचैम ने कहा है कि सरकार का एक मई से 18 साल से अधिक की आयु के सभी लोगों के लिए कोविड टीकाकरण को खोलने से मुश्किलों से जूझ रहे लोगों का भरोसा कायम करने में मदद मिलेगी। एसोचैम ने मंगलवार को बयान में कहा कि टीकाकरण तेज होने से कोविड-19 के मामले घटेंगे और अर्थव्यवस्था का पुनरुद्धार रफ्तार पकड़ सकेगा। इससे लोगों की आजीविका को बचाने में मदद मिलेगी। चैंबर ने कहा कि और वैक्सीन 'कैंडिडेट' को मंजूरी की प्रक्रिया तेज करना टीकाकरण को व्यापक करने की दृष्टि से एक निर्णायक उपाय है। एसोचैम ने कहा, ''टीकाकरण की आयु को घटाकर 18 साल करने से मुश्किल हालात का सामना कर रहे लोगों का भरोसा कायम किया जा सकेगा।''

अब तेजी से निपटेंगे चेक बाउंस के मामले, सुप्रीम कोर्ट ने दिया यह आदेश

नई दिल्ली। एजेसी

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को चेक बाउंस के मामलों को जल्दी से निपटाए जाने की व्यवस्था के लिए कई निर्देश जारी किए और केंद्र से कहा कि वह कानून में संशोधन कर के ऐसे प्रावधान करे कि यदि किसी एक व्यक्ति के विरुद्ध एक साल में एक से अधिक मामले दर्ज किए गए हो तो ऐसे मामलों की सुनवाई एक साथ की जा सके। शीर्ष अदालत ने पिछले साल मार्च में चेक बाउंस के लंबित मामलों की भारी संख्या का संज्ञान लिया था। 31 दिसंबर, 2019 को देश में ऐसे लंबित कुल 2.31 करोड़ आपराधिक मामलों में चेक बाउंस से जुड़े मामलों की संख्या 35.16 लाख थी। मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पांच न्यायधीशों की संविधान पीठ ने एक साझा आदेश में 'आपराधिक अदालतों पर बोझ कम करने' के लिए कदम उठाए। पीठ ने उच्च न्यायालयों से कहा कि वे चेक का अनादर होने के मामलों की सुनवायी करने वाले मजिस्ट्रेटों को 'प्रक्रिया विषयक निर्देश' जारी करें और कहें कि वे परक्राम्य लिखत कानून की धारा 138 के तहत शिकायतों को फौरी सुनवाई के स्थान पर समन जारी करके सुनवाई

करने के अपने निर्णय का कारण अदालत के रिकार्ड पर दर्ज करें।

केंद्र कर सकता है कानून में संशोधन

दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के तहत सरसरी सुनवाई में अभियुक्त अपना दोष नहीं मानता है, तो मजिस्ट्रेट सबूत दर्ज करके तुरंत निर्णय सुना सकता है। लेकिन सीआरपीसी के तहत समन जारी कर सुनवाई करने की प्रक्रिया में न्यायिक अधिकारी को कार्यवाही पूरी करनी और सबूत रिकॉर्ड करना होगा। पीठ ने कहा, 'हम सिफारिश करते हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऐक्ट की धारा 219 में विहित प्रतिबंधों के बावजूद एक व्यक्ति द्वारा 12 महीने की अवधि के भीतर अधिनियम की धारा 138 के तहत किए गए एक से अधिक अपराधों की सुनवाई एक साथ किए जाने के प्रावधान हेतु अधिनियम में उपयुक्त संशोधन किए जाएं।' पीठ ने इस मुद्दे पर अदालत के मित्र अधिवक्ता की इसी तरह की सिफारिश का उल्लेख किया। न्यायालय ने इस इस सुझाव पर ध्यान दिया कि चेक बाउंस संबंधी कानून में केंद्र द्वारा उपयुक्त संशोधन किया जा सकता है ताकि जहां एक ही तरह के उद्देश्य के लिए चेक जारी किए गए हो वहां 'कार्यवाही की बहुलता से बचा जा सके।' मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बोबडे ने पीठ की ओर से 27 पन्नों का आदेश लिखते हुए कहा, अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायतें मिलने पर जांच कराई जाएगी ताकि सुनवायी अदालत के न्यायिक अधिकार की भौगोलिक सीमा से बाहर रहने वाले आरोपी के खिलाफ इस तरह की एक साथ कार्रवाई का पर्याप्त आधार तय किया जा सके।

समिति करेगी विचार

आदेश में कहा गया है कि अभियुक्त को बुलाने से पहले जांच कराने के लिए शिकायतकर्ता की ओर से गवाहों के साक्ष्य को शपथ पत्र पर लेने की अनुमति दी जाएगी और 'उपयुक्त मामलों में मजिस्ट्रेट गवाहों की गवाही दर्ज करने पर जोर दिए बिना जांच को दस्तावेजों की छान-बीन तक सीमित रख सकता है।' न्यायालय ने सुनवायी अदालतों के लिए प्रक्रिया संबंधी ऐसे निर्देश जारी करने का निर्देश दिया है जिसके तहत एक व्यक्ति के खिलाफ धारा 138 के तहत किसी एक शिकायत की सुनवायी के सिलसिले में जारी सम्मन को उस अदालत के समक्ष उसके खिलाफ ऐसे सभी मामलों के लिए जारी सम्मन माना जाए। पीठ ने कहा है कि उसके शुक्रवार के निर्णय में चेक बाउंस से जुड़े जो मुद्दे बाकी रह गए गए हैं उन पर मुंबई उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरसी चव्हाण की अध्यक्षता वाली समिति विचार करेगी। न्यायालय ने इस समिति का गठन 10 मार्च को किया था।

डीपीआईआईटी ने एसी, एलईडी बल्ब के लिये पीएलआई योजना को अधिसूचित किया

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

उद्योग एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने एसी और एलईडी बल्ब के लिये उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) को अधिसूचित कर दिया है। योजना के तहत ऐसे उत्पादों का विनिर्माण करने वाली कंपनियों को समर्थन दिया जायेगा जो उत्पाद मौजूदा समय में भारत में नहीं बनते हैं। विभाग ने कहा है कि केवल कल-पुर्जे जोड़ कर सामान बनाने को प्रोत्साहित नहीं किया जायेगा बल्कि जो कंपनियां मूल और आधारभूत उपकरणों, कलपुर्जों में निवेश करेंगी उन्हें उच्च प्राथमिकता दी जायेगी।

सरकार ने इस माह की शुरुआत में एयर कंडीसनर्स (एसी) और एलईडी बल्ब जैसे सामानों के उत्पादन के लिये पीएलआई योजना को मंजूरी दी थी। इसके लिये 6,238 करोड़ रुपये का बजट का प्रावधान है। योजना को 2021-29 तक लागू किया जायेगा। डीपीआईआईटी की अधिसूचना के मुताबिक कैबिनेट सेक्रटरी की अध्यक्षता वाली सचिवों का उच्चाधिकार प्राप्त समूह पीएलआई योजना पर नजर रखेगा। योजना के तहत दी जाने वाली राशि को लेकर समय समय पर उसकी समीक्षा करेगा। सभी पीएलआई में समानता बनाये रखेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि जो भी खर्च हो वह तय योजना के दायरे में ही हो। सचिवों के समूह को एसी और एलईडी बल्ब के क्षेत्र को पीएलआई के तहत आवंटित कुल 6,238 करोड़ रुपये की सकल योजना के भीतर तौर- तरीकों में किसी भी प्रकार के बदलाव का अधिकार होगा। इसमें कहा गया है कि पीएलआई योजना का लाभ प्रति लाभार्थी उसकी बिक्री में अतिरिक्त वृद्धि के आधार पर लागू होगा। एक साल पहले यानी आधार वर्ष 2019- 20 के विनिर्मित सामान के कर भुगतान के बाद शुद्ध बिक्री के आधार पर इसकी गणना होगी। हालांकि, इसकी ऊपरी सीमा भी होगी। ''तैयार सामानों की एसेम्बली करने मात्र को प्रोत्साहन नहीं दिया जायेगा। योजना के तहत कंपनियों का चयन कलपुर्जों के भारत में विनिर्माण करने अथवा ऐसे उत्पादों की छोटे स्तर पर एसेम्बली को प्रोतसाहित किया जायेगा जिनका भारत में पर्याप्त क्षमता में उत्पादन नहीं होता है।'' योजना के तहत देश में एसी के विभिन्न कलपुर्जों जैसे कि कॉपर ट्यूब, एल्यूमीनियम फायल और कंप्रेसर्स और एलईडी बल्ब के मामले में एलईडी चिप, पैकेजिंग, रेसिसटेंर, आईसीस और फ्यूज आदि विनिर्माण करने वाली कंपनियों को समर्थन मिलेगा। अधिसूचना में प्रोतसाहन योजना को लेकर अन्य चीजों को भी स्पष्ट किया गया है।

अमेरिका के सांसदों ने भारत में बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा को बढ़ाकर 74 प्रतिशत करने का स्वागत किया

वाशिंगटन। एजेंसी

अमेरिका के दो प्रभावशाली सांसदों ने भारत में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) सीमा को 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत किये जाने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि भारत सरकार के इस फैसले से द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में और मजबूती आयेगी। भारतीय संसद ने पिछले महीने ही बीमा संशोधन विधेयक 2021 को पारित किया। इसके जरिये भारतीय बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा को बढ़ाया गया। कांग्रेसमैन ब्राड शेरमन और स्टीव चाबोट ने कहा, ''भारतीय बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा को 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत किये जाने के एक प्रावधान को शामिल किये जाने से हम काफी उत्साहित हैं।'' इसकी लंबे समय से प्रतीक्षा की जा रही थी। इसके कारण भारतीय उपभोक्ताओं और कारोबार के लिये बीमा कवरेज को विस्तार देने की प्रतिबद्धता के समक्ष लंबे समय से गतिरोध बना हुआ था।'' अमेरिका में भारतीय राजदूत तरनजीत सिहं संधू को लिखे एक पत्र में दोनों सांसदों ने कहा है कि भारत के हाल के सालाना बजट में प्रस्तावित पहल से भारत के महत्वकांक्षी अवसंरचना लक्ष्य के लिये पूंजी की उपलब्धता बढ़ाने में मदद मिलेगी।

डीजीसीए ने विदेशों में पंजीकृत मैक्स 737 विमानों को भारतीय क्षेत्र में उड़ान की अनुमति दी

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने विदेशों में पंजीकृत बोइंग 737 मैक्स विमान को भारतीय क्षेत्र के ऊपर से उड़ान की अनुमति दे दी है। इथियोपिया में एक दर्दनाक हादसे के बाद मार्च, 2019 से इस विमान को खड़ा कर दिया गया था। एजेंसी की अनुमति के बाद बोइंग 737 मैक्स भारतीय क्षेत्र के ऊपर से उड़ सकता है। डीजीसीए के आदेश में कहा गया है कि इस विमान को पट्टे पर लेनी वाली कंपनियों को अपने खड़े 737 मैक्स विमान को नियामक की अनुमति के बाद भारत से बाहर ले जानी की अनुमति होगी। डीसीजीए ने 13 मार्च, 2019 को सभी बोइंग मैक्स विमानों को भारत में प्रतिबंधित कर दिया था। इथियोपिया एयरलाइंस का 737 मैक्स विमान अदीस अबाबा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस हादसे में चार भारतीयों सहित 157 लोग मारे गए थे। नियामक ने मंगलवार को कहा कि वह 737 मैक्स विमानों को खड़ा करने, मरम्मत या रखरखाव के लिए ले जाने को विशेष उड़ान परमिट जारी करेगा। विमान विनिर्माता बोइंग मार्च, 2019 से 737 मैक्स विमानों में सुधार कर रही है जिससे डीजीसीए सहित उसे विभिन्न देशों में यात्री उड़ानों के परिचालन की अनुमति फिर मिल सके। डीजीसीए ने कहा कि 13 मार्च, 2019 को लगाए गए प्रतिबंध के दायरे में विदेशों में पंजीकृत 737 मैक्स विमान नहीं आएंगे।

Oxygen Supply

प्लांट में तैयार होकर मरीज तक कैसे पहुंचती है ऑक्सीजन, जानें पूरी प्रक्रिया

इंदौर। एजेंसी

देश में कोरोना की दूसरी लहर (Second Wave of Coronavirus) का कहर चरम पर है। कोरोना के मरीजों की संख्या इतनी तेजी बढ़ रही है कि अस्पतालों में बेड कम पड़ गए हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर (Oxygen Cylinder) की कमी (Shortage of Oxygen Supply) पैदा हो गई है। वह ऑक्सीजन जो सांस लेने के लिए जरूरी है, उसके सिलेंडर की कमी हाहाकार पैदा कर रही है। इस बीच देश के स्टील प्लांटों ने अपने यहां ऑक्सीजन की खपत कम कर अस्पतालों को लिक्विड ऑक्सीजन (Liquid Oxygen) सप्लाई करना शुरू कर दिया है। वहीं सरकार ने 6177 मीट्रिक टन ऑक्सीजन अलग-अलग राज्यों को उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। इसके अलावा ट्रेनों में ऑक्सीजन सिलेंडर या टैंकरों का परिवहन शुरू करने का निर्णय लिया गया है। आइए जानते हैं कि इंसानों के साथ-साथ पशु-पक्षियों के सांस लेने के लिए भी जरूरी ऑक्सीजन, इसके प्लांट्स में कैसे बनती है और कैसे यह प्लांट से मरीजों तक पहुंचती है।

क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन प्रॉसेस से बनती है ऑक्सीजन

सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह की कंपनियां ऑक्सीजन प्लांट लगा सकती हैं। ऑक्सीजन गैस क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन प्रॉसेस के जरिए बनती है। यानी हवा में मौजूद विभिन्न गैसों को अलग-अलग किया जाता है, जिनमें से एक ऑक्सीजन भी है। क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन प्रॉसेस में हवा को फिल्टर किया जाता है, ताकि धूल-मिट्टी को हटाया जा सके। उसके बाद कई चरणों में हवा को कंप्रेस (भारी दबाव डालना) किया जाता है। उसके बाद कंप्रेस हो चुकी हवा को मॉलीक्यूलर छलनी एडजॉर्बर (adsoRer) से ट्रीट किया जाता है, ताकि हवा में मौजूद पानी के कण, कार्बन डाई ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन को अलग किया जा सके।

यूं मिलता है लिक्विड ऑक्सीजन

इस पूरी प्रक्रिया से गुजरने के बाद कंप्रेस हो चुकी हवा डिस्टिलेशन कॉलम में जाती है, जहां पहले इसे ठंडा किया जाता है। यह प्रक्रिया एक plate fin heat exchanger & expansion tuRine के जरिए होती है और उसके बाद 185 डिग्री सेंटीग्रेट (ऑक्सीजन का उबलने का स्तर) पर उसे गर्म किया जाता है, जिससे उसे डिस्टिल्ड किया जाता है। बता दें कि डिस्टिल्ड की प्रक्रिया में पानी को उबाला जाता है और उसकी भाप को कंडेंस कर के जमा कर लिया जाता है। इस प्रक्रिया को अलग-अलग स्टेज में कई बार किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अर्गन जैसी गैसें अलग-अलग हो जाती हैं। इसी प्रक्रिया के बाद लिक्विड ऑक्सीजन और गैस ऑक्सीजन मिलती है।

इलाज में लिक्विड ऑक्सीजन होता है इस्तेमाल

पूरे देश में तकरीबन 500 फैक्ट्रियां हैं, जो हवा से ऑक्सीजन बनाती हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट में जिस तरह की ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है, वह लिक्विड ऑक्सीजन होती है। प्लांट्स में पूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद बनकर तैयारी होने वाली लिक्विड ऑक्सीजन को तय तापमान पर बड़े-बड़े क्रायोजेनिक टैंकरों में भरकर डिस्ट्रीब्यूटर्स के जरिए हॉस्पिटल्स में सप्लाई किया जाता है।

पाइप और सिलेंडर दोनों होते हैं हॉस्पिटल में इस्तेमाल

कुछ बड़े हॉस्पिटल्स में सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन केबिन या टैंक होता है, जहां से जिस बेड पर ऑक्सीजन की जरूरत है वहां पाइपलाइन के जरिए इसकी सप्लाई होती है। छोटे हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन बड़े-बड़े सिलेंडरों में पहुंचाई जाती है, फिर पाइपलाइन के जरिए मरीज के बेड तक पहुंचती है। बेहद छोटे हॉस्पिटल्स, जहां पाइपलाइन की सुविधा नहीं है, वहां ऑक्सीजन के छोटे सिलेंडर मरीज के बेड के पास लगाए जाते हैं।

घरों में भी रखे जा रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर

आजकल घरों में भी ऑक्सीजन सिलेंडर रखे जा रहे हैं। लोग ऑक्सीजन सिलेंडर बेचने वाले या रीफिल करने वाले से इसे खरीद कर घर में रख लेते हैं। रीफिल करने वाले, टैंकर से लिक्विड ऑक्सीजन मंगवाते हैं। फिर अपने यहां स्टोर करके छोटे सिलेंडरों में रीफिल करते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर में वैपराइज्ड गैस होती है। लिक्विड को वैपर फॉर्म में सिलेंडर में भरा जाता है।

भारत की ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता

एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में 7000 मीट्रिक टन से अधिक मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन करने की क्षमता है। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, 12 अप्रैल को भारत में मेडिकल ऑक्सीजन की खपत 3842 मीट्रिक टन थी। यह मेडिकल ऑक्सीजन की दैनिक उत्पादन क्षमता का 54 फीसदी है। केंद्र की योजना है कि वह दूर-दराज के इलाकों में 100 अस्पतालों की पहचान करेगा, जो अपने खुद के लिए ऑक्सीजन बना सकते हैं। अस्पताल सप्लाई को स्टोर करने के लिए विशाल भंडारण टैंक बना रहे हैं जो कम से कम 10 दिनों तक चल सकते हैं।

अगले महीने भारत बायोटेक कोविड-19 रोधी टीके की तीन करोड़ खुराक का उत्पादन करेगी

नयी दिल्ली। एजेंसी

देश में टीकाकरण अभियान को समर्थन देने के लिए भारत बायोटेक अगले महीने कोविड-19 टीके 'कोवैक्सिन' की तीन करोड़ खुराक का उत्पादन करेगी। कंपनी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक कृष्णा एल्ला ने मंगलवार को यह जानकारी दी। मार्च में कंपनी ने कोवैक्सिन की 1.5 करोड़ खुराक का उत्पादन किया था।

वैक्सीन विनिर्माता ने बयान में कहा कि उसने कोवैक्सिन की सालाना उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 70 करोड़ खुराक कर लिया है। एल्ला का यह बयान ऐसे समय आया है जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन विनिर्माताओं से टीके का उत्पादन बढ़ाने को कहा है, जिसमें कम से कम समय में सभी भारतीयों का टीकाकरण किया जा सके। सरकार ने सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) तथा भारत बायोटेक को भविष्य में आपूर्ति बढ़ाने के लिए 4,500 करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान करने की भी अनुमति दी है।

एल्ला ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कंपनी बेंगलुरु में दो नए वैक्सीन संयंत्रों को शुरू करने जा रही है। कंपनी ने शुरुआत में एक संयंत्र से उत्पादन शुरू किया था। अब कंपनी के हैदराबाद में चार संयंत्र परिचालन में हैं। एल्ला ने कहा, "पिछले महीने हमने डेढ़ करोड़ खुराक का उत्पादन किया था। इस महीने हम दो करोड़ खुराक का उत्पादन कर रहे हैं। अगले महीने हम तीन करोड़ खुराक का उत्पादन करेंगे। उसके बाद सात से साढ़े सात करोड़ खुराक का उत्पादन किया जाएगा।"

रिजर्व बैंक की मुद्रा बाजार मे गतिविधियां संतुलित, विदेशी मुद्रा का नहीं कर रहा संग्रहः वाणिज्य सचिव

नयी दिल्ली (एजेंसी)। भारत ने अमेरिका के वित्त विभाग द्वारा देश को मुद्रा व्यवहार में छेड़छाड़ करने वालों की निगरानी सूची में डालने के आधार को खारिज कर दिया। भारत ने मंगलवार को कहा कि विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में केंद्रीय बैंक की गतिविधियां संतुलित हैं और यह विदेशी मुद्रा भंडार का संग्रह नहीं कर रहा। महामारी की शुरुआत के बाद से भारत को सोमवार को दूसरी बार इस निगरानी सूची में डाला गया है। केंद्रीय बैंक द्वारा डॉलर की खरीद जीडीपी के पांच प्रतिशत से अधिक रहने को इसकी वजह बताया गया है। अमेरिकी वित्त विभाग ने कहा है कि यह सीमा दो प्रतिशत रहनी चाहिये।वाणिज्य सचिव अनूप वधावन ने कहा कि इस तरह की निगरानी सूचियां हाल में बननी शुरू हुई हैं। यह केंद्रीय बैंक के नीतिगत क्षेत्र में हस्तक्षेप है। "व्यक्तिगत रूप से मुझे इसके पीछे तार्किक या आर्थिक तर्क समझ नहीं आता।" उन्होंने कहा कि भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 500 से 600 अरब डॉलर के बीच स्थिर है। भारत चीन की तरह विदेशी मुद्रा का संग्रह नहीं कर रहा है।

उद्योग जगत ने आर्थिक गतिविधियां जारी रखने की प्रधानमंत्री के बयान की सराहना की

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

उद्योग जगत ने आर्थिक गतिविधियां जारी रखने के बारे में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बयान का मंगलवार को स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वह कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिये उठाये जाने वाले कदमों के साथ यह सुनिश्चित करेंगे कि आर्थिक गतिविधियां कम-से-कम प्रभावित हों। उद्योग जगत ने कहा कि प्रधानमंत्री का बयान काफी उत्साहजनक है और इससे भरोसा जगता है कि जीवन और आजीविका दोनों प्राथमिकता में ऊपर है। राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर अपनी टिप्पणी में उद्योग मंडल सीआईआई के उपाध्यक्ष संजीव बजाज ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कोविड महामारी की रोकथाम के लिये स्पष्ट रूप से रणनीति को रखा है। उन्होंने कहा, "यह सुनिश्चित करने की घोषणा की गयी कि आर्थिक गतिविधियां कम-से-कम प्रभावित हों। यह काफी उत्साहजनक है। इससे भरोसा जगता है कि जीवन और आजीविका दोनों प्राथमिकता में ऊपर है।" बजाज ने कहा कि सरकार का अगले चरण के टीकाकरण के लिये टीका उत्पादन बढ़ाने को लेकर कोष में वृद्धि का निर्णय देश के स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था में भरोसा को बढ़ाता है। पीएचडी चैंबर ने कहा कि प्रधानमंत्री के संबोधन से कोरोना के खिलाफ अभियान को लेकर लोगों के बीच विश्वास बढ़ेगा। उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री ने जो उपाय सुझाये हैं, वे उत्साहजनक हैं और प्रवासी मजदूरों, व्यापार, उद्योग तथा अर्थव्यवस्था पर कोविड के प्रभाव को कम करेगा... एक मई, 2021 से 18 साल से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण जल्दी ही महामारी के प्रभाव को कम करेगा।" नारेडको (नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल) के राष्ट्रीय अध्यक्ष निरंजन हीरानंदानी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आर्थिक गतिविधियों को बनाये रखने की जरूरत पर बल दिया है, जो स्वागत योग्य है। प्राधिकरण भी नागरिकों में घबराहट को कम करने को लेकर कदम उठा रहे हैं।

मर्यादित राष्ट्रमंगल भाव को लोकमंगल हित जनमानस तक पहुँचाते श्रीराम- डॉ. पुनीत द्विवेदी

मर्यादा पुरुषोत्तम लोक कल्याण के भाव को जन-जन तक पहुँचाने वाले श्रीराम भारतीय और विश्व समाज में पूजित हैं। ज्ञातव्य है कि 'त्याग ही राम की महिमा है' और राम त्याग के पर्याय। जन्म से महापरिनिर्वाण तक श्री राम का जीवन त्याग एवं संघर्षों का जीवन रहा है। जीवन के प्रत्येक क्षण में त्याग भाव के साथ संघर्षों में मनुष्य जीवन को महान उदाहरण बनाकर लोक कल्याण के द्वारा राष्ट्र को परंवैभव की ओर अग्रसर करने का मार्ग श्री राम ने प्रशस्त किया है। मूल्यों के साथ जीवन प्रबंधन के द्वारा कैसे लोकमंगल के भाव को प्रमुखता दी जा सकती है, इसे दशरथ नंदन राजा राम ने चरितार्थ किया है। जीवन के प्रत्येक पड़ाव पर मनुष्य जीवन में नैतिक मूल्यों की प्रासंगिकता के पर्याय रहे हैं श्री राम। विभिन्न विचारधाराओं के साथ सामन्जस्य स्थापित कर जगती के कल्याण के लिये अपने जीवन को उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत करने वाले जन-नायक रहे हैं श्री राम। ज्ञान और शील के माध्यम से विश्व कल्याण एवं राष्ट्रीय एकता के लिये एक तपस्वी की भाँति भारतवर्ष में अलख जगाने की शक्ति हैं श्री राम। जिन्होंने बाल्यकाल से ही समाज कल्याण हित अपने जीवन को राष्ट्र के नाम समर्पित कर हम सबके प्रेरणापुरुष बने। श्री राम का जीवन प्रत्येक भारतीय एवं विश्व समुदाय के लिये भी सदा प्रासंगिक रहा है और रहेगा क्योंकि श्री राम 'वसुधैव कुटुम्बकम्' के भाव को पूरे विश्व में प्रचारित-प्रसारित करने के लिये कृतसंकल्पित रहे हैं। तत्कालीन हिंदु समाज को एकजुट कर सुमंगलम् के लक्ष्यों को साध कर समाज के सुदृढ़ समायोजन के कारक रहे हैं श्री राम। समाज में उपेक्षित वर्ग के कल्याण हित, उनके जीवन स्तर को सुदृढ़ और सुंदर बनाने हित अपने जीवन में संघर्षों को चुनकर आगे बढ़ने वाले समाज सुधारक रहे हैं श्री राम। भील, केवट, अहल्या, बानर, गिद्ध, राक्षस अर्थात् मनुष्य ही नहीं अपितु प्राणी मात्र के कल्याण के लिये अपने जीवन को अर्पित कर देने वाले महापुरुष रहे हैं श्री राम। माता शबरी के जूठे बेरों का सेवन कर, निषाद राज गुह को हृदय से लगाकर, केवट के प्रेम से विह्वल हो उपेक्षित हिंदु भील समुदाय को मुख्य धारा से जोड़ने के लिये सामाजिक समरसता के प्रणेता रहे हैं श्री राम। आईये, रामनवमी के पावन अवसर पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन से सीख लेकर वर्तमान एवं भविष्य की पीढ़ियों को सम्यक और संस्कारित बनायें। लोक मंगल ही सनातन हिंदु समाज की विशेषता है जिसमें जननायक, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जीवन सदा प्रेरणादायी रहा है और रहेगा।

(लेखक डॉ.पुनीत कुमार द्विवेदी (शिक्षाविद्) मॉडर्न ग्रुप ऑफ़ इंस्टीट्यूशन्स, इंदौर में प्रोफ़ेसर एवं समूह निदेशक की भूमिका में कार्यरत हैं)

श्रीराम जी की पवित्र जन्म कथा, रामनवमी पर पढ़ने से मिलता है मनचाहा आशीष

रामायण और रामचरित मानस हमारे पवित्र ग्रंथ हैं। तुलसीदास जी ने श्री राम को ईश्वर मान कर रामचरितमानस की रचना की है किन्तु आदिकवि वाल्मीकि ने अपने रामायण में श्री राम को मनुष्य ही माना है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को राम के राज्यभिषेक के बाद समाप्त कर दिया है वहीं आदिकवि श्री वाल्मीकि ने अपने रामायण में कथा को आगे श्री राम के महाप्रयाण तक वर्णित किया है।महाराजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ आरंभ करने की ठानी। महाराज की आज्ञानुसार श्यामकर्ण घोड़ा चतुरंगिनी सेना के साथ छुड़वा दिया गया। महाराज दशरथ ने समस्त मनस्वी, तपस्वी, विद्वान ऋषि-मुनियों तथा वेदविज्ञ प्रकाण्ड पण्डितों को यज्ञ सम्पन्न कराने के लिये बुलावा भेज दिया। निश?चित समय आने पर समस्त अभ्यागतों के साथ महाराज दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ जी तथा अपने परम मित्र अंग देश के अधिपति लोभपाद के जामाता ऋंग ऋषि को लेकर यज्ञ मण्डप में पधारे। इस प्रकार महान यज्ञ का विधिवत शुभारंभ किया गया। सम्पूर्ण वातावरण वेदों की ऋचाओं के उच्च स्वर में पाठ से गूंजने तथा समिधा

की सुगन्ध से महकने लगा।

समस्त पण्डितों, ब्राह्मणों, ऋषियों आदि को यथोचित धन-धान्य, गौ आदि भेंट कर के सादर विदा करने के साथ यज्ञ की समाप्ति हुई। राजा दशरथ ने यज्ञ के प्रसाद चरा(खीर) को अपने महल में ले जाकर अपनी तीनों रानियों में वितरित कर दिया। प्रसाद ग्रहण करने के परिणामस्वरूप तीनों रानियों ने गर्भधारण किया।जब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में सूर्य, मंगल शनि, वृहस्पति तथा शुक्र अपने-अपने उच्च स्थानों में विराजमान थे, कर्क लग्न का उदय होते ही महाराज दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ से एक शिशु का जन्म हुआ जो कि नील वर्ण, चुंबकीय आकर्षण वाले, अत्यन्त तेजोमय, परम कान्तिवान तथा अत्यंत सुंदर था। उस शिशु को देखने वाले देखते रह जाते थे। इसके पश्चात् शुभ नक्षत्रों और शुभ घड़ी में महारानी कैकेयी के एक तथा तीसरी रानी सुमित्रा के दो तेजस्वी पुत्रों का जन्म हुआ।सम्पूर्ण राज्य में आनन्द मनाया जाने लगा। महाराज के चार पुत्रों के जन्म के उल्लास में गन्धर्व गान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगीं। देवता अपने विमानों में बैठ कर पुष्प वर्षा करने लगे। महाराज ने उन्मुक्त हस्त से राजद्वार पर आए भाट, चारण तथा आशीर्वाद देने वाले ब्राह्मणों और याचकों को दान दक्षिणा दी। पुरस्कार में प्रजा-जनों को धन-धान्य तथा दरबारियों को रत्न, आभूषण प्रदान किए गए। चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार महर्षि वशिष्ठ के द्वारा किया गया तथा उनके नाम रामचन्द्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखे गए।आयु बढ़ने के साथ ही साथ रामचन्द्र गुणों में भी अपने भाइयों से आगे बढ़ने तथा प्रजा में अत्यंत लोकप्रिय होने लगे। उनमें अत्यन्त विलक्षण प्रतिभा थी जिसके परिणामस्वरू अल्प काल में ही वे समस्त विषयों में पारंगत हो गए। उन्हें सभी प्रकार के अस्त्र-शस्त्रों को चलाने तथा हाथी, घोड़े एवं सभी प्रकार के वाहनों की सवारी में उन्हें असाधारण निपुणता प्राप्त हो गई। वे निरन्तर माता-पिता और गुरुजनों की सेवा में लगे रहते थे। उनका अनुसरण शेष तीन भाई भी करते थे। गुरुजनों के प्रति जितनी श्रद्धा भक्ति इन चारों भाइयों में थी उतना ही उनमें परस्पर प्रेम और सौहार्द भी था। महाराज दशरथ का हृदय अपने चारों पुत्रों को देख कर गर्व और आनन्द से भर उठता था।

राम नवमी के दिन पूजा का सबसे शुभ समय कौन सा है

रामनवमी के दिन मां दुर्गा और श्री राम-मां सीता का पूजन किया जाता है.... इस दिन का महत्व इतना ज्यादा है कि लोग नये घर, दुकान या प्रतिष्ठान में नवमी के दिन ही पूजा-अर्चना कर प्रवेश करते हैं... इस दिन मां दुर्गा के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री की उपासना की जाती है....

श्री रामनवमी 2021

बुधवार, 21 अप्रैल 2021

राम नवमी मध्याह्न शुभ मुहूर्तः 11 बजकर 02 मिनट से 13 बजकर 38 मिनट तक

अवधिः 02 घंटे 36 मिनट

सीता नवमी : 21 मई 2021

शुक्रवार

राम नवमी मध्याह्न का सबसे शुभ क्षणः 12 बजकर 20 मिनट

नवमी तिथि प्रारम्भः 21अप्रैल 2021 को 00 बजकर 43 मिनट से

नवमी तिथि समाप्तः 22 अप्रैल 2021 को 00 बजकर 35 मिनट तक

राम एवं दुर्गा नवमी जानिए नवमी तिथि के खास 6 महत्व

चैत्र नवरात्रि में कई घरों में नवमी को दुर्गा माता की पूजा होती है। इस दिन राम नवमी भी होती हैं। आओ जानते हैं कि नवमी तिथि का ज्योतिष में क्या महत्व है।

1. **तिथि कार्य महत्व :** नवमी तिथि चन्द्र मास के दोनों पक्षों में आती है। इस तिथि की स्वामिनी देवी माता दुर्गा है। यह तिथि रिक्ता तिथियों में से एक है। रिक्ता अर्थात खाली। इस तिथि में किए गए कार्यों की कार्यसिद्धि रिक्त होती है। यहीं कारण है कि इस तिथि में समस्त शुभ कार्य वर्जित माने गए हैं। मात्र माता की पूजा ही फलदायी होती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी अक्षय एवं आंवला नवमी के नाम से मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन होता है और आंवले के वृक्ष की पूजा भी की जाती है। अश्विन माह की शारदीय नवरात्रि में दुर्गा की पूजा होती है।
2. **तिथि वार महत्व :** यह तिथि चैत्रमाह में शून्य संज्ञक होती है और इसकी दिशा पूर्व है। शनिवार को सिद्धदा और गुरुवार को मृत्युदा मानी गई है। अर्थात शनिवार को किए गए कार्य में सफलता मिलती है और गुरुवार को किए गए कार्य में सफलता की कोई गारंटी नहीं।
3. **दुर्गा नवमी :** नवमी तिथि के शुक्ल पक्ष में दुर्गा की पूजा शुभ लेकिन शिव पूजन अशुभ है। हालांकि कृष्ण नवमी को शिव पूजन कर सकते हैं। जीवन में यदि कोई संकट है अथवा किसी प्रकार की अड़चनें आने से काम नहीं हो पा रहा है तो जातक दुर्गा नवमी के दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करके विधिवत समापन करें और कन्याओं को भोज कराएं।
4. **राम नवमी :** चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को राम नवमी के रूप में उत्साह और हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्रीराम का पूजन और वंदन करने से सुख, समृद्धि और शांति बढ़ती है। साथ ही संतान सुख की प्राप्ति होती है।
5. **क्या ना खाएं :** नवमी के दिन लौकी खाना निषेध है, क्योंकि इस दिन लौकी का सेवन गौ-मांस के समान माना गया है। इस दिन कड़ी, पूरणपौल, खीर, पूरी, साग, भजिये, हलवा, कद्दू या आलू की सब्जी बनाई जा सकती है।
6. **नवमी में जन्मे जातक :** नवमी तिथि में जन्म लेने वाला जातक देवों का भक्त होता और पुत्रवान होता है। जातक अपने बाहुबल से विजय पाने की कोशिश करता है। हालांकि उसमें त्याग और समर्पण होता है। इस तिथि में जन्मा जातक धनार्जन में कुशल होता है।

खाद्य तेलों के बीच मक्का रिफाइंड तेल भी बना रहा है अपनी जगह, चार साल में दोगुना हुआ उत्पादन

नयी दिल्ली। एजेंसी

सरसों, सोयाबीन, बिनौला और मूंगफली तेलों के बीच मक्का रिफाइंड तेल भी अब अपनी जगह बनाता हुआ दिख रहा है। पिछले चार-पांच साल के दौरान देश में मक्का रिफाइंड तेल का उत्पादन करीब दोगुना हो गया है। मक्का रिफाइंड तेल की ज्यादा खपत फिलहाल गुजरात, महाराष्ट्र और कुछ अन्य राज्यों में अधिक है जबकि उत्तर भारत के राज्यों में धीरे-धीरे इसका चलन बढ़ रहा है। तेल-तिलहन कारोबार के जानकार पवन गुप्ता का कहना है कि इस साल बिनौला तेल में माल की कमी है। सोयाबीन तेल का इस्तेमाल कुछ कम हुआ है वहीं सूरजमुखी तेल अब महंगा पड़ने लगा है। इस लिहाज से मक्का रिफाइंड तेल की मांग बढ़ी है।

मक्का रिफाइंड तेल और खल से जुड़े एक अन्य व्यापारी अर्पित गुप्ता का कहना है कि मक्का रिफाइंड तेल का भाव 140 रुपये किलो के आसपास है, जबकि बिनौला तेल 148 रुपये किलो और मूंगफली तेल 160 रुपये किलो तक पड़ता है। उनका कहना है कि नमकीन, मिठाई और इसी तरह के अन्य उत्पाद बनाने वाली प्रमुख कंपनियां जहां पहले बिनौला, सोयाबीन तेल का इस्तेमाल करते थीं, वहीं अब वह मक्का रिफाइंड तेल का अधिक इस्तेमाल कर रही हैं। बिनौला और सरसों की तरह एक्सपैलर से सीधे मक्की खल निकलती है जिसकी अच्छी मांग है।

बिनौला खल में जहां सात प्रतिशत तेल होता है वहीं मक्की खल में 12 से 14 प्रतिशत तक तेल की मात्रा होती है। मक्का खल पशुओं के लिये काफी उपयोगी बताई गई है। इस लिहाज से इसकी मांग काफी बढ़ी है। देश में चार साल पहले जहां 5,000 टन प्रति महीना मक्का रिफाइंड तेल का उत्पादन होता था वहीं अब यह बढ़कर आठ से 10 हजार टन महीना तक पहुंच गया है। इस स्थिति को देखते हुये यह कहा जा सकता है कि सरसों, सोयाबीन, मूंगफली तेलों के बीच मक्का रिफाइंड तेल भी अपनी जगह बनाने लगा है।

जॉनसन एंड जॉनसन ने भारत में अपने कोविड-रोधी टीके के क्लिनिकल परीक्षण के लिये मंजूरी मांगी

नयी दिल्ली। एजेंसी

दवा और चिकित्सा उपकरण बनाने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने मंगलवार को कहा कि उसने भारत के औषधि नियामक से अपने एक खुराक वाले टीके के चिकित्सीय परीक्षण के लिये अनुमति मांगी है। इसका मकसद स्थानीय नियमन का अनुपालन करना है। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (यूएसएफडीए) ने फरवरी में जॉनसन एंड जॉनसन के कोविड-19 रोधी टीके को मंजूरी दे दी थी। इस टीके की एक ही खुराक की जरूरत पड़ती है। कंपनी ने एक बयान में कहा, ''जॉनसन एंड जॉनसन स्वास्थ्य प्राधिकरणों और दुनिया के बेहतरीन वैज्ञानिकों के साथ मिलकर दुनिया भर में अपने कोविड-रोधी टीके जॉनसन के आपात उपयोग को लेकर जरूरी आंकड़े उपलब्ध करा रही है।'' उल्लेखनीय है कि सरकार ने पिछले सप्ताह दूसरे देशों में उत्पादित उन सभी टीकों के आपात उपयोग के लिये तेजी से मंजूरी देने का निर्णय किया, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन या अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन या जापान में नियामकों से मंजूरी मिली है। सरकार के इस निर्णय के बाद जॉनसन एंड जॉनसन ने परीक्षण की मंजूरी मांगी है। बयान के अनुसार, ''हमने भारतीय औषधि महानियंत्रक से अपने एकल खुराक वाले कोविड रोधी टीका जॉनसन के क्लिनिकल परीक्षण को पूरा करने के लिये मंजूरी को लेकर आवेदन दिया है ताकि स्थानीय नियमन को पूरा किया जा सके।'' कंपनी के टीके को रेफ्रिजरेटर तापमान पर रखा जा सकता है।

एमएसएमई क्षेत्र की वृद्धि में डिजिटलीकरण की महत्वपूर्ण भूमिकाः गडकरी

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रम (एमएसएमई) मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि विपणन और विनिर्माण क्षेत्र के डिजिटलीकरण की देश के लघु एवं मझोले उपक्रमों के कारोबार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। उन्होंने ऐसी प्रौद्योगिकियों पर जोर दिया जिससे आर्थिक रूप से सक्षम एमएसएमई देश के ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में अपना विस्तार कर पाएं। गडकरी ने मंगलवार को माइक्रोसॉफ्ट के एक कार्यक्रम में कहा, ''एमएसएमई को डिजिटल करना महत्वपूर्ण विषय है। डिजिटल ऐसा समाधान है जिसके जरिये हम अपनी प्रणाली को पारदर्शी और समयबद्ध बना सकते हैं।''

उन्होंने कहा कि विपणन या मार्केटिंग एमएसएमई के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। कई छोटी कंपनियों ने ऑनलाइन मार्केटिंग शुरू की है जिससे शानदार नतीजे दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा डिजिटलीकरण विनिर्माण क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने प्रौद्योगिकी क्षेत्र का आह्वान किया वह एमएसएमई क्षेत्र को प्रक्रियाओं में मदद करे।

मंत्री ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र की देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 30 प्रतिशत हिस्सेदारी है। इसके अलावा निर्यात में उसका 48 प्रतिशत का हिस्सा है और उसने 11 करोड़ रोजगार का सृजन किया है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य जीडीपी में एमएसएमई की हिस्सेदारी बढ़ाकर 40 प्रतिशत और निर्यात में 60 प्रतिशत करने का है। इसके अलावा सरकार क्षेत्र में पांच करोड़ नए रोजगार के अवसरों का भी सृजन करना चाहती है। गडकरी ने कहा, ''सरकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा ग्रामीण, कृषि, आदिवासी क्षेत्रों तथा 115 आकांक्षी जिलों में एमएसएमई का विकास करने का है।'' उन्होंने कहा कि यह ऐसा क्षेत्र है जिसका जीडीपी में योगदान काफी कम है। ''ऐसे में हमें ऐसी प्रौद्योगिकी ढूंढनी चाहिए जिससे आर्थिक रूप से मजबूत एमएसएमई गांवों, ग्रामीण इलाकों, कृषि और आदिवासी इलाकों में विस्तार कर सकें।''

आर्थिक गतिविधियों पर दिखने लगा है स्थानीय लॉकडाउन का असर, टीकाकरण भी घटाः रिपोर्ट

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

देश में लगातार दूसरे दिन कोविड-19 संक्रमण के 2.5 लाख से अधिक मामले आए हैं। इस चिंताजनक स्थिति के बीच एक रिपोर्ट में आगाह किया गया है कि लोगों की आवाजाही और कुछ कारोबार क्षेत्रों पर सीमित अंकुशों के बावजूद आर्थिक परिदृश्य निराशाजनक दिख रहा है। बिजली की खपत और ई-वे जीएसटी बिल संग्रहण पहले की तुलना में सुस्त पड़ा है। रिपोर्ट में टीकाकरण की रफ्तार को तेज करने पर जोर दिया गया है। साप्ताहिक आधार पर टीकाकरण सुस्त हुआ है। क्रिसिल के मंगलवार को जारी एक नोट में कहा गया है कि संक्रमण के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और अब अधिक से अधिक राज्य स्थानीय स्तर पर लोगों की आवाजाही और कारोबार पर अंकुश लगा रहे हैं। बिजली की खपत से लेकर जीएसटी ई-वे बिल संग्रहण में इसका असर दिख रहा है। क्रिसिल ने कहा कि राहत की बात यह है कि विनिर्माण और निर्माण गतिविधियों का परिचालन हो रहा है। ज्यादातर राज्यों में सामाजिक दूरी उपायों के साथ यात्रा और घूमने-फिरने से जुड़ी सेवाओं की अनुमति है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चिंता की बात टीकाकरण की सुस्त रफ्तार है। 18 अप्रैल को समाप्त सप्ताह में प्रतिदिन प्रत्येक 10 लाख लोगों पर 2,408 को टीका लगाया गया। इससे पिछले यानी 11 अप्रैल को समाप्त सप्ताह में यह आंकड़ा 2,554 का था। रिपोर्ट कहती है कि 18 अप्रैल तक 45 से 65 आयु वर्ग में सिर्फ 16.4 प्रतिशत आबादी को टीका लगा है। वहीं 65 साल और उससे अधिक के आयुवर्ग में 33.1 प्रतिशत लोगों को टीका लगाया गया है। भारत में महामारी की स्थिति काफी खराब है। 12 से 18 अप्रैल के दौरान प्रतिदिन दो लाख से अधिक नए संक्रमण के मामले आए। इससे भारत संक्रमण के नए मामलों में ब्राजील को पीछे छोड़कर सबसे आगे निकल गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि महाराष्ट्र में 18 अप्रैल को समाप्त सप्ताह में संक्रमण के नए मामलों में काफी गिरावट आई है। वहीं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली में इनमें उल्लेखनीय इजाफा हुआ है। संक्रमण के नए मामलों में 11 अप्रैल को समाप्त सप्ताह में महाराष्ट्र की हिस्सेदारी 42.3 प्रतिशत थी जो 18 अप्रैल को समाप्त सप्ताह में घटकर 28.2 प्रतिशत पर आ गई।

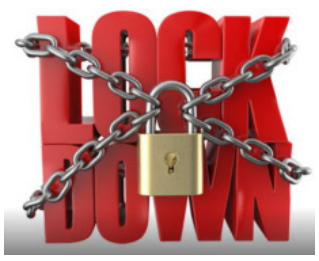

कोयला गैसीफिकेशन के जरिये उत्पादित यूरिया के लिए सब्सिडी योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तालचेर फर्टिलाइजर्स लि. (टीएफएल) द्वारा कोयला गैसीफिकेशन के जरिये उत्पादित यूरिया के लिए एक विशिष्ट सब्सिडी योजना को मंजूरी दी है। टीएफएल का गठन 2015 में हुआ था। यह गेल इंडिया लि., कोल इंडिया लि., राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि. और फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (एफसीआईएल) का संयुक्त उद्यम है। टीएफएल द्वारा एफसीआईएल के पूर्ववर्ती तालचेर संयंत्र का पुनरुद्धार किया जा रहा है। इसके तहत वह ओडिशा में 12.7 लाख टन सालाना स्थापित क्षमता का नया यूरिया कारखाना लगा रही है। टीएफएल की यूरिया परियोजना की अनुमानित लागत 13,277.21 करोड़ रुपये है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) की बैठक के बाद संवाददाताओं को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीसीईए ने पहली बार देश में कोयला गैसीफिकेशन की नवोन्मेषी प्रौद्योगिकी को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि कोयला गैसीफिकेशन संयंत्र रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोयला कीमतों में ज्यादा उतार-चढ़ाव नहीं होता है और देश में यह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। गोयल ने कहा, ''भारत में कोयले का बड़ा भंडार है लेकिन गैस पर्याप्त नहीं है। ''कोयले को गैस में बदलने और फिर गैस को यूरिया में बदलने से भारत आत्मनिर्भर बन सकेगा।'' उन्होंने कहा कि तालचेर संयंत्र के जरिये यूरिया के उत्पादन को प्राकृतिक गैस पर निर्भरता घटेगी। इससे देश का एलएनजी आयात बिल कम होगा। उन्होंने कहा इससे सालाना 12.7 लाख टन यूरिया आयात कम करने में मदद मिलेगी जिससे विदेशी मुद्रा बचाई जा सकेगी। उन्होंने कहा कि भारत में अपनी तरह की इस पहली परियोजना की लागत 13,277 करोड़ रुपये बैठेगी। भारत में यूरिया सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला उर्वरक है।

सीरम इंस्टीट्यूट का बड़ा ऐलान

राज्यों को 400 रुपये में मिलेगा कोविशील्ड का एक डोज

नई दिल्ली। एजेंसी

पुणे स्थित दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने वैक्सीन की कीमतों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। बुधवार को कंपनी ने कहा है कि राज्य सरकार को 400 रुपये प्रति डोज की दर पर वैक्सीन मिलेगी। इसके अलावा निजी अस्पतालों में वैक्सीन की कीमत 600 रुपये प्रति डोज होगी। कंपनी ने उत्पादन के बाद राज्य और केंद्र सरकार के बीच वैक्सीन को 50-50 प्रतिशत बांटने का फैसला किया है। देश में कोरोना महामारी का कहर जारी है। इन दिनों महामारी की दूसरी लहर का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रही है। कोरोना बढ़ते मामलों के बीच बुधवार को कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बड़ा फैसला लिया हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड वैक्सीन की कीमतों की घोषणा कर दी है। कंपनी अब ये दवाएं सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को बेच पाएगी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से मिली जानकारी के अनुसार राज्य सरकारों के लिए प्रति डोज़ की कीमत 400 रुपये और निजी अस्पतालों के लिए प्रति डोज़ की कीमत 600 रुपये होगी। बता दें कि कंपनी के मुताबि?क भारत सरकार के निर्देशों के बाद यह घोषणा की गई हैं। अभी सरकारी अस्पतालों में यह मुफ्त में लग रही है जबकि निजी अस्पतालों में इसकी कीमत 250 रुपये है। बढ़ाई जाएगी टीकों की उत्पादन क्षमता सीरम इंस्टीट्यूट ने सीईओ अदार पूनावाला ने कहा कि अगले दो महीनों के लिए हम टीकों की उत्पादन क्षमता बढ़ाएंगे। हमारी क्षमता का 50 फीसदी टीके भारत सरकार के टीकाकरण अभियान को दिए जाएंगे और बाकी 50 फीसदी राज्य सरकारों और निजी अस्पतालों के लिए होंगे। कंपनी ने विदेशी वैक्सीन के दामों की भारतीय वैक्सीन के दाम से तुलना की है। देश की सबसे बड़ी वैक्सीन मैन्युफैक्चर कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा है कि पांच महीनों के बाद वैक्सीन रिटेल और फ्री ट्रेड में कहीं भी मिलने लगेगी। सीरम इंस्टीट्यूट ने कोवीशील्ड का प्रोडक्शन करती है। यह वैक्सीन एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मिलकर डेवलप किया है। विदेशी वैक्सीनों के मुकाबले भारतीय वैक्सीन सस्ती दुनिया में वैक्सीनों की कीमत के मुकाबले भारत में वैक्सीन की कीमत काफी कम है। अमेरिकी वैक्सीनों की कीमत 1500 रुपये से अधिक है जबकि रूसी वैक्सीन की क़ीमत 750 रुपये और चीनी वैक्सीन की क़ीमत 750 रुपए है। उन्होंने कहा कि अभी हर कंपनी को वैक्सीन की आपूर्ति करना संभव नहीं है और उन्हें सरकारी और निजी अस्पतालों के जरिए वैक्सीन लेनी चाहिए। 4-5 महीने बाद वैक्सीन रीटेल और ओपन मार्केट में उपलब्ध होगी। सरकार का अहम फैसला सरकार ने दो दिन पहले एक अहम बैठक में यह फैसला लिया था कि 1 मई 2021 से 18 साल से ज्यादा उम्र के हर शख्स को वैक्सीन लगाया जा सकेगा। पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर से संक्रमण के 2,95,041 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,56,16,130 पहुंच गई है। देश में कोरोनावायरस संक्रमण की दूसरी लहर ज्यादा खतरनाक है। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक, कुल 1,56,16,130 संक्रमितों में से एक्टिव केसों की संख्या 21,57,538 है और 1,32,76,039 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। पिछले एक दिन में इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 2023 रही। मरने वालों की यह अब तक कि सबसे बड़ी संख्या है। इस महामारी के कारण 1,82,553 लोगों की मौत हो चुकी है।

बड़ी राहत

Remdesivir API और इंजेक्शन की किल्लत होगी दूर, भारत ने आयात शुल्क हटाया

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

कोरोना वायरस के कहर के बीच रेमडेसिविर को लेकर पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना केस बढ़ने से इसकी मांग में इतनी तेजी आई है कि चारों तरफ इसकी किल्लत होने लगी है। इस बीच केंद्र सरकार ने एक राहत भरा फैसला लिया है। देश ने एंटी-वायरल दवा रेमेडिसिविर पर आयात शुल्क हटा दिया है। जिसका उपयोग वर्तमान में कोविड -19 रोगियों के इलाज के लिए किया जाता है। मंगलवार देर रात जारी एक अधिसूचना में दवा के निर्माण के लिए इस्तेमाल होने वाली दवा सामग्री के आयात पर शुल्क को हटा दिया। यह कदम घरेलू उपलब्धता को बढ़ाने और इंजेक्शन की लागत को कम करने में मदद करेगा। साथ ही सरकार के इस कदम से न सिर्फ इसकी किल्लत दूर होगी, बल्कि कीमत भी कम होगी।

सरकार ने मंगलवार को रेमडेसिविर, उसके कच्चे माल और एंटीवायरल दवा बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अन्य घटकों पर सीमा शुल्क माफ कर दिया। राजस्व विभाग की ओर से जारी बयान में कहा गया कि केंद्र सरकार ने जिन वस्तुओं पर शुल्क माफ किया गया है, उनमें रेमेडिसविर के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्री (एपीआई), रेमेडिसविर इंजेक्शन और बीटा साइक्लोडोडेक्स्ट्रिन शामिल हैं। आयात शुल्क में यह छूट 31 अक्टूबर तक लागू रहेगी।

वहीं, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर बताया है कि कोरोना के इलाज में कारगर मानी जा रहे रेमडेसिविर इंजेक्शन को बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल (Remdesivir API) के आयात पर कोई शुल्क नहीं वसूला जाएगा। इसके अलावा, रेमडेसिविर इंजेक्शन के आयात को भी ड्यूटी फ्री कर दिया गया है। केंद्र सरकार की इस घोषणा से आने वाले दिनों में देश में ये दवा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने की उम्मीद की जा सकती है।

इस बीच केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि अगले 15 दिनों में एंटी वायरल दवा रेमडेसिवर का उत्पादन दोगुना कर दिया जाएगा। बता दें कि एंटी वायरल दवा रेमडेसिवर को लेकर कई राज्यों से कमी की खबर आ रही है। केंद्रीय मंत्री मांडविया ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो संदेश में कहा था कि भारत सरकार देश में रेमेडिसविर इंजेक्शन के उत्पादन को बढ़ाने और कम कीमत पर उपलब्ध कराने के सभी प्रयास कर रही है। वर्तमान में, रेमेडिसवीर की प्रतिदिन 150,000 शीशियों का उत्पादन प्रति दिन किया जा रहा है और, अगले 15 दिनों में, उत्पादन को दोगुना करके 300,000 शीशियां प्रत्येक दिन किया जाएगा।

लॉकडाउन से घबराए लोग, कर रहे हैं जरूरी सामान की खरीदारी

बढ़ी रेडी-टू-ईट और रेडी-टू-कुक खाने की मांग

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

देश में एक बार फिर कोरोना संकट गहराने के साथ राज्यों द्वारा लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं। इसको देखते हुएउपभोक्ताओं ने जरूरी सामानों का संग्रह करना शुरू कर दिया है जिसके चलते बाजार में हर तरफ घबराहट भरी खरीदारी देखने को मिल रही है। उपभोक्ताओं खाने-पीने की जरूरी सामान की खरीदारी किराना स्टोर पर लाइन लगा कर रहे हैं। इसके साथ ही ई-कॉमर्स और ऑनलाइन ग्रॉसरी एप के जरिये भी ऑर्डर बुक कर रहे हैं। ई-कॉमर्स और ग्रॉसरी एप पर ऑर्डर का आलम यह है कि ज्यादातर सामान के लिए लंबी प्रतिक्षा अवधि या आउट ऑफ स्टॉक दिखाए जा रहे हैं। सिर्फ किराना या ई-कॉमर्स पर ही नहीं बल्कि दवा और दारू की दुकान पर खरीदारी की भीड़ उमड़ गई है। वहीं, कारोबारियों का कहना है कि पिछले कुछ दिन के खाने-पीने का सामान, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले उत्पादों की जमकर खरीदारी हो रही है।

किन-किन उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ी

नोएडा स्थित ग्रॉसरी शॉप हैप्पी होम के मैनेजर गौरी शंकर ने बताया कि बीते पांच दिनों में जिन उत्पादों की मांग बढ़ी है उनमें खाद्य तेल, आटा, मसाला, फल, सब्जियां, स्नैक्स, फ्रोजन फूड्स, ड्राई फूड्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, बेबी फूड्स, हाइजीन प्रोडक्ट्स, च्यवनप्राश, जूस और खाने-पीने के जरूरी समान शामिल है। लोग एक बार फिर से इन सामानों की तेजी से खरीदकर स्टॉक कर रहे हैं। इसके चलते रोजना बिक्री करीब दोगुनी हो गई है।

ग्रॉसरी एप ने डिलीवरी की अवधि बढ़ाई

कई शहरों में लॉकडाउन लगने के साथ ऑनलाइन ग्रॉसरी एप पर ऑर्डर दोगुने से अधिक बढ़ गए हैं। ग्रोफर्स के एक प्रवक्ता के अनुसार, एप पर 80 फीसदी का उछाल पैकेज्ड फूड जैसे रेडी-टू-ईट और रेडी-टू-कुक, फ्रोजेन फूड्स की मांग में 500 फीसदी, डिब्बाबंद दूध की मांग में और 100 फीसदी की वृद्धि हाइजीन उत्पाद में आई है। ग्रोफर्स के अलावा बिग बास्केट, नेचर बास्केट, ऑनडोर आदि पर भी मांग बड़ी तेजी से बढ़ी है। इसके चलते इन एप ने डिलीवरी की अवधि बढ़ा दी है। वहीं, कई उपभोक्ताओं का कहना है कि अभी से कई जरूरी समान यहां पर ऑउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं।

ई-कॉमर्स नहीं ले रहा टीवी-फोन आदि के ऑर्डर

लॉकडाउन लगने के साथ ई-कॉमर्स साइट भी कपड़े, टीवी, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आदि सामान के ऑर्डर लेना बंद कर दिया है। फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील, मिंत्रा सहित कई दूसरी ई-कॉमर्स वेबसाइट से मोबाइल से लेकर दूसरे सामान बुक करने पर संदेश आ रहा है कि सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक, मौजूदा समय में हम सिर्फ जरूरी सामान की ही डीलिवरी कर रहे हैं।

पिछले साल से स्थिति अभी बेहतर

कारोबारियों का कहना है कि कोरोना संकट बढ़ने के साथ उपभोक्ताओं द्वारा जरूरी सामानों की खरीदारी तेजी से बढ़ी है लेकिन पिछले साल जैसी स्थिति नहीं है। इस बार ग्राहकों को विश्वास है कि रिटेलर ऑनलाइन ऑर्डर, एप या फोन के जरिये ऑर्डर मिलने पर भी उनके घर के दरवाजे पर आपूर्ति कर सकेंगे।

आर्थिक गतिविधियों पर रोक से हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे कारोबार

कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के मद्देनजर विभिन्न राज्यों में स्थानीय स्तर पर लगाए गए प्रतिबंधों के बीच रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आरएआई) ने मंगलवार को कहा कि आर्थिक गतिविधियों पर रोक से कारोबार हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे और लाखों लोगों का रोजगार चला जाएगा। खुदरा संगठन ने कहा कि पिछले साल लॉकडाउन के दौरान ऐसे ही हालत पैदा हुए थे। इसलिए अब सरकार को चाहिये कि गैर-आवश्यक या गैर-खाद्य खुदरा कारोबार और मॉल को सख्त निगरानी के तहत काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए। आरएआई के सीईओ कुमार राजगोपालन ने एक बयान में कहा, गैर-आवश्यक या गैर-खाद्य खुदरा दुकानों और मॉल को बंद करना समाधान नहीं है। पिछले साल कारोबार को हुए नुकसान को ध्यान में रखते हुए इस स्तर पर आर्थिक गतिविधि को बंद करने से व्यवसाय स्थायी रूप से बंद हो जाएंगे, जिससे लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसकी जगह सख्त निगरानी में सुरक्षा और स्वच्छता के सभी नियमों और शारीरिक दूरी के मानदंडों का पालन सुनिश्चित करते हुये कारोबार को खुला रखना चाहिए और उन पर पूर्ण पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। राजगोपालन ने कहा कि शॉपिंग केन्द्रों सहित देश भर में संगठित क्षेत्र के खुदरा कारोबारी पूरी सफलता के साथ कामकाज की मानक परिचालन प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं और इसलिये उन्हें सख्त निगरानी में रखते हुये काम करने की अनुमति मिलनी चाहिए।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुनः प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।